

22 लोगों की मौत, 55 घायल क्रेन से टकरा गई ट्रेन

थाईलैंड के नखोन रत्चासिमा प्रांत में बुधवार को यात्री ट्रेन के क्रेन से टकरा जाने से कम से कम 22 लोगों की मौत हो गई और 55 अन्य घायल हो गए। स्थानीय मीडिया रिपोर्टों के अनुसार दुर्घटना स्थानीय समयानुसार सुबह लगभग 09:05 बजे उस समय हुई, जब बैंकॉक से उबोन रत्चाथानी जा रही यात्री ट्रेन निर्माण कार्य में लगी क्रेन से टक्कर के बाद पटरी से उतर गयी।

आपातकालीन बचाव दल तुरंत मौके पर पहुंचे और हाइड्रोलिक कटिंग टूल का इस्तेमाल कर मलबे में फंसे यात्रियों को बाहर निकालना शुरू कर दिया। घायल यात्रियों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पतालों में पहुंचा दिया गया है।



थाईलैंड के उप प्रधानमंत्री और परिवहन मंत्री पिपहत रचलाकितप्रकार्ण ने कहा कि उन्होंने एजेंसियों को पारदर्शी एवं व्यापक जांच करने के निर्देश दिए हैं ताकि दुर्घटना के कारणों का पता लगाया जा सके तथा भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके।

भ्रष्टाचार कानून पर बंटे जज, बंटा हुआ फैसला आने के बाद बड़ी बैंच को भेजा मामला

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को भ्रष्टाचार के मामलों में सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ जांच से पहले परमिशन लेने की अनिवार्यता पर सुनवाई हुई। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस विश्वनाथन की बैंच ने इस पर स्प्लिट वर्डिक्ट (बंटा हुआ फैसला) सुनाया। मामला भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) की धारा 17ए की संवैधानिक वैधता से जुड़ा है। इसमें किसी भी सरकारी कर्मचारी के खिलाफ जांच करने से पहले सरकार की परमिशन लेना जरूरी है। इसी को लेकर विवाद है। सुनवाई में जस्टिस नागरत्ना ने कहा कि धारा 17ए असंवैधानिक है। किसी भी जांच के लिए पहले परमिशन लेना जरूरी नहीं। वहीं, जस्टिस विश्वनाथन ने कहा कि धारा 17 संवैधानिक रूप से वैध है। इस प्रावधान को खत्म करने का मतलब हथाने के पानी के साथ बच्चे को फेंकने जैसा होगा। जस्टिस विश्वनाथन ने यह भी कहा कि इस प्रावधान को खत्म करना और इसका इलाज बीमारी से भी ज्यादा नुकसानदेह साबित होगा। बशर्ते जांच की मंजूरी लोकपाल या राज्य लोकायुक्त के जरिए तय की जाए। जस्टिस नागरत्ना और जस्टिस विश्वनाथन की अलग-अलग राय के चलते अब मामला सीजेआई सूर्यकांत के पास भेजा गया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चीफ जस्टिस इस मुद्दे पर सुनवाई के लिए बड़ी बैंच गठित करेंगे, जो अंतिम फैसला देगी। दरअसल सेंटर फॉर पब्लिक इंटेरेस्ट लिटिगेशन एनजीओ ने जनहित याचिका दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से प्रशांत भूषण ने सुप्रीम कोर्ट ने दलील दी कि यह प्रावधान भ्रष्टाचार विरोधी कानून को कमजोर करता है, क्योंकि सरकार से अक्सर जांच की मंजूरी नहीं मिलती।

मोदी सरकार ने मनरेगा पर चलाया बुलडोजर, सोनिया ने बोला हमला

नई दिल्ली: कांग्रेस की चेयरपर्सन और पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मनरेगा बचाओ संग्राम के तहत एक वीडियो जारी कर केंद्र की मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने और उस पर बुलडोजर चलाने का गंभीर आरोप लगाया है। उन्होंने ये भी कहा कि ये कानून गरीबों, बेरोजगारों और वंचितों के हितों पर सीधा हमला है। सोनिया गांधी ने मंगलवार को मनरेगा बचाओ संग्राम के अंतर्गत वीडियो जारी कर याद दिलाया कि 20 साल पहले डा. मनमोहन सिंह के प्रधानमंत्री काल में मनरेगा कानून सर्वसम्मति से संसद में पास हुआ था। उन्होंने इसे एक क्रांतिकारी कदम बताया, जिसने परिवारों के पलायन को रोका और ग्रामीणों को रोजगार का कानूनी हक दिया। मनरेगा ने करोड़ों गरीब परिवारों को जीवनयापन का सहारा प्रदान किया और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती दी। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले 11 सालों में मोदी सरकार ने गरीबों, बेरोजगारों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा कानून से सिर्फ महात्मा गांधी जी का नाम ही नहीं हटाया गया, बल्कि इस पर बुलडोजर चलाया गया। विपक्ष से बिना किसी सलाह-मशविर के मनमाने ढंग से बदलाव किए गए। अब किसको कितना, कैसे और कहां रोजगार मिलेगा, ये सब जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा लाने में कांग्रेस का बड़ा योगदान था, लेकिन ये कभी पार्टी से जुड़ा मामला नहीं रहा- ये देशहित और जनहित से जुड़ा मुद्दा है। मोदी सरकार द्वारा मनरेगा को कमजोर करके करोड़ों किसानों, गरीबों, भूमिहीनों पर हमला किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने घोषणा की, इस हमले का मुकाबला हमें मिलकर करना होगा। 20 साल पहले अपने गरीब भाइयों-बहनों को रोजगार का अधिकार दिलाने के लिए मैं भी लड़ी थी, अब इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ।



मोदी सरकार ने गरीबों, बेरोजगारों और वंचितों के हितों को नजरअंदाज किया। उन्होंने कहा कि मनरेगा कानून से सिर्फ महात्मा गांधी जी का नाम ही नहीं हटाया गया, बल्कि इस पर बुलडोजर चलाया गया। विपक्ष से बिना किसी सलाह-मशविर के मनमाने ढंग से बदलाव किए गए। अब किसको कितना, कैसे और कहां रोजगार मिलेगा, ये सब जमीनी हकीकत से दूर दिल्ली में बैठकर सरकार तय करेगी। उन्होंने कहा कि मनरेगा लाने में कांग्रेस का बड़ा योगदान था, लेकिन ये कभी पार्टी से जुड़ा मामला नहीं रहा- ये देशहित और जनहित से जुड़ा मुद्दा है। मोदी सरकार द्वारा मनरेगा को कमजोर करके करोड़ों किसानों, गरीबों, भूमिहीनों पर हमला किया जा रहा है। सोनिया गांधी ने घोषणा की, इस हमले का मुकाबला हमें मिलकर करना होगा। 20 साल पहले अपने गरीब भाइयों-बहनों को रोजगार का अधिकार दिलाने के लिए मैं भी लड़ी थी, अब इस काले कानून के खिलाफ लड़ने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ।

ISRO को बड़ा झटका, PSLV-C62 रास्ता भटका नहीं कर सका उपग्रहों को कक्षाओं में स्थापित

श्रीहरिकोटा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (कपफ) का ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान-सी62 (दरुछ-362) सोमवार को देश के नवीनतम जासूसी सैटेलाइट द्वाअन्वेष्णा (ईओएस-एन1) और उसके साथ भेजे गये अन्य उपग्रहों को उनकी तय कक्षाओं में स्थापित करने में विफल रहा। इस उपग्रह अन्वेष्णा को रक्षा अनुसंधान विकास संगठन (डीआरडीओ) ने बनाया था और इसके साथ कुछ अन्य भारतीय एवं विदेशी संस्थाओं के 15 अन्य छोटे उपग्रह भी इस रॉकेट से भेजे गए थे। इसरो अध्यक्ष डॉ. वी. नारायणन ने घटना की जानकारी देते हुए कहा कि रॉकेट को तीसरे चरण के अंत में गड़बड़ी का सामना करना पड़ा। उन्होंने यहा७ मिशन कंट्रोल सेंटर से एक संक्षिप्त संबोधन में कहा कि इसके बाद रॉकेट के उड़ान पथ में विचलन हुआ। उनके अनुसार, इसरो इसके डेटा का विश्लेषण करने के बाद ही सही जानकारी प्रदान करेगा। पीएसएलवी रॉकेट यहां बने सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) के पहले लॉन्च पैड से भारतीय समयानुसार सुबह लगभग 10.18 बजे लॉन्च हुआ। पीएसएलवी रॉकेट के इस वेरिएंट का इस्तेमाल पहली बार 24 जनवरी, 2019 को माइक्रोसैट आर उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने के लिए किया गया था और सोमवार को इसने पांचवीं बार उड़ान भरी। यह रॉकेट ब्लास्ट-ऑफ के तुरंत बाद धीरे-धीरे आसमान की ओर ऊपर उठा, उसकी निचले हिस्से से मोटी नारंगी लौ निकल रही थी, उसने गति पकड़ी और ऊपर की तरफ धुआं छोड़ता जा रहा था। इस लिफ्ट-ऑफ के लगभग चार मिनट बाद रॉकेट का तीसरा स्टेज चालू हुआ और बाद में इंजन बंद हो गया। इस पीएसएलवी-सी62 का वजन 260 टन और इसकी लंबाई 44.4 मीटर थी। यह पीएसएलवी एक चार-चरण/इंजन वाला रॉकेट है जो ठोस और तरल ईंधन द्वारा बारी-बारी से संचालित होता है, जिसमें शुरूआती उड़ान के क्षणों के दौरान अधिक बल



देने के लिए पहले चरण से छह बूस्टर मोटर जुड़े होते हैं। गौरतलब है कि बीते साल भी इसरो के दो मिशन फेल हुए थे। इसमें पहला मिशन 18 मई, 2025 को पीएसएलवी-सी61 से भेजा गया था। इसमें ईओएस-09, एक सिंथेटिक अपरचर रखर वाला पृथ्वी अवलोकन उपग्रह था जो बीच रास्ते में ही फेल हो गया। इसके पहले 29 जनवरी, 2025 को जीएसएलवी-एफ15, एक पाइरो वाल्व की खराबी के कारण अपने एनवीएस-02 नेविगेशन उपग्रह को निर्धारित कक्षा में पहुंचाने में विफल रहा। इससे पहले भी 2021 में, भारत ने एक और रणनीतिक उपग्रह जीआईएसएटी-1 खो दिया क्योंकि उसके रॉकेट जीएसएलवी-एफ10 का क्रायोजेनिक स्टेज चालू नहीं हो पाया। 2017 में एक और उपग्रह-नेविगेशन उपग्रह आईआरएनएसएस-1एच-भी फेल हो गया था क्योंकि पीएसएलवी की हीट शील्ड अलग नहीं हुई। इसरो ने बाद में इस समस्या का कारण पाइरो सेपरेशन सिस्टम में खराबी बताया।

ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों को बड़ा झटका, ट्रंप ने लगाया 25% शुल्क

वाशिंगटन। अमरीका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को ईरान के साथ कारोबार जारी रखने वाले देशों पर 25 प्रतिशत शुल्क लगाने की घोषणा की। राष्ट्रपति ट्रंप ने यह घोषणा ऐसे समय में की जब ईरान में सरकार-विरोधी प्रदर्शन जारी हैं। ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्विटर पर एक पोस्ट में दोहराया कि यह फैसला हतकाल प्रभाव सेह लागू होगा और इस बात पर जोर दिया कि यह ह्आदेश अंतिम और निर्णायक है। उन्होंने कहा, ह् कोई भी देश जो इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के साथ व्यापार कर रहा है उस देश पर यह फैसला तत्काल प्रभाव से लागू होगा। अमेरिका के साथ किए जाने वाले किसी भी और सभी व्यापार पर 25 प्रतिशत शुल्क देना होगा। यह आदेश अंतिम और निर्णायक है। ट्रंप लगातार चेतावनी देते रहे हैं कि यदि देशव्यापी विरोध प्रदर्शन जारी रहे तो अमरीका को ईरान के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है। इस बीच उन्होंने यह भी खुलासा किया कि तेहरान ने बातचीत के लिए अमरीका से संपर्क किया है। जब उनसे पूछा गया कि क्या ईरान बातचीत चाहता है, तो ट्रंप ने कहा, ह्वां, वे चाहते हैं। उन्होंने कहा कि ईरान ने कल बातचीत के लिए फोन किया। ईरान के नेताओं ने फोन किया। वे बातचीत करना चाहते हैं। मुझे लगता है कि वे अमेरिका से थक चुके हैं। ईरान बातचीत चाहता है। अमरीकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि हालांकि एक बैठक की व्यवस्था की जा रही है लेकिन जमीनी हालात अमरीका को बातचीत से पहले ही कार्रवाई करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। इस बीच, रिपब्लिकन सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने 25 प्रतिशत शुल्क लगाने के ट्रंप के फैसले की सराहना की और इसे ईरान के नेतृत्व को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने की दिशा में ह्बेहद प्रभावशाली ह्दम बताया। ग्राहम ने सोशल मीडिया एक्स पर एक पोस्ट में लिखा, ह्दृप, आज आपके कदमों के जरिए इस शासन को आर्थिक रूप से अलग-थलग करने में आपका निर्णायक नेतृत्व बेहद प्रभावशाली है। प्रदर्शनकारियों के समर्थन और इस शासन को यह स्पष्ट संदेश देने का आपका वादा कि आप ह्त्याओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे, ने इस कट्टर शासन की स्थापना के बाद से सबसे बड़े जन-आंदोलन को जन्म दिया है। मेरा मानना है कि ईरानी शासन सभी सीमाएं पर करते हुये बड़ी संख्या में अपने ही लोगों को मार रहे हैं और आपके नेतृत्व का ध्ता दिया जा रहा है। अब निर्णायक सैन्य कार्रवाई का समय है। ह्आष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले का भारत पर भी बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत ईरान के साथ निर्यात और आयात दोनों के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध बनाए हुए है। भारत पहले से ही अमेरिका को अपने निर्यात पर 50 प्रतिशत शुल्क का सामना कर रहा है, जिसमें से 25 प्रतिशत शुल्क को अमेरिका भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद से जोड़ता है। अमरीका का कहना है कि इससे रूस के यूक्रेन युद्ध को वित्तीय मदद मिलती है। गौरतलब है कि भारत और ईरान प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं और हाल के वर्षों में भारत, ईरान के पांच सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल रहा है। अमरीका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता न्यूज एजेंसी के अनुसार अमरीका की ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 646 हो गई है।



करते हुये बड़ी संख्या में अपने ही लोगों को मार रहे हैं और आपके नेतृत्व का ध्ता दिया जा रहा है। अब निर्णायक सैन्य कार्रवाई का समय है। ह्आष्ट्रपति ट्रंप के इस फैसले का भारत पर भी बड़ा असर पड़ सकता है, क्योंकि भारत ईरान के साथ निर्यात और आयात दोनों के माध्यम से महत्वपूर्ण व्यापारिक संबंध बनाए हुए है। भारत पहले से ही अमेरिका को अपने निर्यात पर 50 प्रतिशत शुल्क का सामना कर रहा है, जिसमें से 25 प्रतिशत शुल्क को अमेरिका भारत द्वारा रूसी तेल की खरीद से जोड़ता है। अमरीका का कहना है कि इससे रूस के यूक्रेन युद्ध को वित्तीय मदद मिलती है। गौरतलब है कि भारत और ईरान प्रमुख व्यापारिक साझेदार हैं और हाल के वर्षों में भारत, ईरान के पांच सबसे बड़े व्यापारिक साझेदारों में शामिल रहा है। अमरीका स्थित मानवाधिकार कार्यकर्ता न्यूज एजेंसी के अनुसार अमरीका की ईरान के साथ व्यापार करने वाले देशों पर 25 प्रतिशत आयात शुल्क लगाने की यह घोषणा ऐसे समय में की गई है जब ईरान में देशव्यापी विरोध प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर कम से कम 646 हो गई है।

संपादकीय

संपादक - मर्तुजा मामाजीवाला

ईरानी नरसंहार के बाद

ईरान में अब बगावत या विद्रोह नहीं, बल्कि नरसंहार जारी है। एक आंकड़ा है कि अभी तक करीब 650 मौतें हो चुकी हैं, जबकि पश्चिमी मीडिया 6000 से अधिक मौतों की खबर दे रहा है। कथित ह्यक्रातिवीरह् इरफान को फांसी की सजा सुनाई गई है। ईरानी पुलिस ने 11,000 से अधिक विद्रोहियों को गिरफ्तार किया है अथवा हिरासत में रखा है। सडकों पर 15-18 लाख विद्रोही आंदोलित हैं। लोग जिंदा जलाए जा रहे हैं। ईरान के रिवोल्यूशनरी गार्ड्स के एक कर्नल की विद्रोहियों ने हत्या कर दी है। मस्जिदें, बैंक, सरकारी इमारतें, पुलिस स्टेशन जलाए गए हैं। गवर्नर आवास भी आगजनी का शिकार हुआ है। ईरानी हुकूमत ने विद्रोहियों को देखते ही गोली मार देने के आदेश जारी किए हैं। विद्रोहियों को ह्यसजा-ए-मौतह् भी दी जा सकती है। इन ऐलानों के बावजूद लाखों युवाओं के हुजूम सुप्रीम धार्मिक नेता खामेनेई का तख्तापलट करने पर आमादा हैं। सडकों पर खामेनेई समर्थक भी फैल गए हैं। आंदोलन महंगाई, बेरोजगारी, आर्थिक पतन, ढहती मुद्रा रियाल आदि के खिलाफ शुरू हुआ था, लेकिन अब उसने अंतरराष्ट्रीय रूप ले लिया है। अमरीकी राष्ट्रपति ट्रंप लगातार ईरानी हुकूमत को धमका रहे हैं कि कभी भी हमला किया जा सकता है। एक ओर अमरीका है, तो दूसरी ओर ईरान के साथ रूस, चीन सरीखी महाशक्तियां हैं। बीच में खबर आई थी कि खामेनेई अपने परिवार और घोर समर्थक 20 लोगों के साथ मॉस्को भाग सकते हैं, लेकिन वह अब भी ईरान के बेहद सुरक्षित ठिकाने के भीतर हैं और बेहद घातक बल के जवान उनकी सुरक्षा में मोचाबंद हैं। ईरान वेनेजुएला नहीं है, लिहाजा ट्रंप किसी मुगालते में न रहें। ईरान एक ताकतवर और प्रशिक्षित सेना वाला देश है। उसके पास परमाणु सम्मत मिसाइल भी है, जिसका एक चित्र मीडिया में दिखाया गया था। ईरान ने ऐलान किया है कि यदि अमरीका ने हमला किया, तो ईरान अपने आसपास के 19 अमरीकी बेसों पर हमला कर उन्हें तबाह कर देगा।

लिहाजा राष्ट्रपति ट्रंप जरा खुद को संयमित रखें और दूसरे देशों को हड़पने की रणनीति फिलहाल शांत कर दें, क्योंकि उनके टैरिफवाद पर सुप्रीम अदालत का फैसला आने वाला है और अमरीका में ही सैकड़ों शहरों में ट्रंप-विरोधी प्रदर्शन जारी हैं। लोकतंत्र में जनता का हुजूम कोई भी करवट ले सकता है। सत्ताएं पलट जाती हैं। बेशक ईरान बहुत तेजी से विपन्नता की ओर बढ़ा है। जनवरी, 2026 में ही वहां की खाद्य मुद्रास्फीति 70-85 फीसदी तक उछल चुकी है। एक डॉलर की कीमत 14.20 लाख ईरानी रियाल हो गई है। गरीबी दर करीब 40 फीसदी है और देश की विकास दर मात्र 0.6 फीसदी है। खाने-पीने की चीजें दुर्लभ हो गई हैं। भारत के संदर्भ में देखें, तो वित्त वर्ष 2024-25 में दोनों देशों का आपसी कारोबार करीब 1.68 अरब डॉलर रहा। भारत को करीब 0.80 अरब डॉलर का व्यावसायिक लाभ हुआ। भारत ईरान को चावल, चीनी, चाय, दवाइयां, इलेक्ट्रोनिक मशीनरी, कृत्रिम फाइबर आदि निर्यात करता है, जबकि ईरान से सूखे मेवे, रसायन, कांच से बने उत्पाद भारत को भेजे जाते हैं। ईरान सबसे अधिक कच्चा तेल आपूर्ति वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। यदि ईरान संकट का असर होर्मुज जलडमरूमध्य तक पहुंचता है, तो वैश्विक तेल आपूर्ति बुरी तरह प्रभावित होगी। दुनिया के करीब 20 फीसदी कच्चे तेल की आपूर्ति इसी रास्ते से होती है। भारत अपनी जरूरत का 80 फीसदी से ज्यादा तेल आयात करता है। ऐसे में तेल महंगा हो सकता है। यही नहीं, ईरान की चाबहार बंदरगाह भारत को पाकिस्तान को बायपास करते हुए अफगानिस्तान, मध्य एशिया और यूरोप तक सीधा व्यापारिक रास्ता देती है। यदि ईरान में अस्थिरता बढ़ती है और चाबहार बंदरगाह प्रभावित, बाधित होती है, तो भारत की भू-आर्थिक रणनीति को बड़ा झटका लग सकता है।

पुलिस वर्दी में चिट्ठे के दागों को मिटाने की सख्ती ने ग्यारह कर्मियों को घर बैठा दिया है। अपनी तरह का उदाहरण पेश करते हुए हिमाचल सरकार ने एक साथ पुलिस कर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की है। जाहिर है चिट्ठे के मनहूस धंधे में ऐसी कई कड़िां हैं, जहां व्यवस्था में छुपे सांप नजर आते हैं। एक बहुत बड़ा तंत्र मिलीभगत पर उतर आया है। नशाखोरी के आलम में पूरी तरह तफतीश हो, तो आसान तरीकों की कमाई में ह्यएक नरकह् काम कर रहा है। आश्चर्य यह कि जिस वर्दी के हवाले से चिट्ठे के खिलाफ अभियान चल रहा है, उसके भीतर भी कई तरह के खलनायक छुपे हैं। चिट्ठा कोई सीढिां चढ़ कर हिमाचल नहीं पहुंचा, बल्कि कानून व्यवस्था के बीच हाथ मिला कर चौकसी की मिट्टी पलीद कर रहा है। यहां सामान्य ड्यूटी में तैनात व सीआईडी की गोपनीयता में शरीक पुलिस कर्मी भी मिले हैं, तो अलग-अलग बटालियनों में नशे के



सरगना सक्रिय रहे हैं। चिट्ठे के खिलाफ हिमाचल सरकार ने हर तरीके, बंदोबस्त, चौकसी, सतर्कता, सामाजिक जवाबदेही और सख्ती के संदेशों से एक जबरदस्त अभियान को अंजाम तक पहुंचाने की ठान ली है। हर दिन पुलिस की ही फाइल से ऐसे मामलों की सूचना परवान चढ़ रही है, तो हर केस हिस्ट्री बता रही है कि चिट्ठे की आपूर्ति में खुराक दर खुराक पहुंचाई जा रही है। कुछ वर्ष पूर्व एक सरकारी वाहन में चिट्ठे की तरह सफेद सामान मिला

था, लेकिन तब यह चीनी का बुरादा साबित हुआ था। हिमाचल के चरित्र में आ रहा खचीर्लापन, दिखावे का भडकीलापन, समाज में अकेलापन और युवा पीढ़ी के प्रति नीतियों का रूखापन, हमें विचित्र परिस्थितियों के गलघोंटू माहौल में कैद कर रहा है। यहां भूमिका सिर्फ पुलिस या पुलिस के डंडे की नहीं, हर घर, मोहल्ले, बस्ती, गांव, शहर और प्रदेश की भी है। नशा दवाई की दुकान पर बोटल चाटते हुए मिलेगा, जंगल में उगी भांग में मिलेगा, तो

यारी-दोस्ती में चिट्ठे की घुसपैठ जैसा दिखेगा। हमें जरूरत ज्यादा अस्पतालों की है या खेल के मैदानों की। हमें जरूरत रोजगार अवसरों की है या सरकारी नौकरी की पोस्टरबाजी ने युवा कल्पना को ही मार दिया है। क्या हमारी शिक्षा की व्याख्या में नौकरी का पाठ्यक्रम इतना उद्बेलित नहीं हो गया कि छात्र जीवन गलत आसरा ढूंढने लगा। चिट्ठे का मनोवैज्ञानिक प्रभाव ही गलत रास्तों पर समाज की टेढ़ी कमर का फायदा

उठा रहा है। अगर सामाजिक, पारिवारिक और व्यवस्थागत विद्रूपताएं न हों, तो कौन इस धंधे में जीवन को असहाय बनाए। इस नशे का एक ही पर्याय है मौत, फिर भी मौत के धंधे में हाथ साफ करते देखे जा रहे हैं। इसकी आपूर्ति ही इसका सेवन है, जहां समाज के भीतर लक्ष्य भी हैं और शिकार भी। ये ग्यारह पुलिस कर्मी धंधे के शिकार हुए या इन्होंने अपनी भूमिका के लक्ष्य में गुनाह को कबूल किया। पुलिस और इसके अधीन होमगार्ड्स जहां भी ड्यूटी निभाते हैं, वहां दोहरे मानदंड या दोहरा चरित्र क्यों सामने आ रहा है। यह मामूली रिश्तत से शुरू होकर असामाजिक तत्वों की गलबहियों में उपजा विनाश बन जाता है। ऐसा क्यों है कि सुरक्षा कर्मियों के पहरों में धार्मिक स्थल भी भ्रष्टाचार के पापड़ बेलना शुरू कर देते हैं। अक्सर ह्यददर्शन करवा देगेह् के पीछे जो संवाद पुलिस का सिपाही या होम गार्ड करता है, उसके पीछे मंदिर के

टीके और प्रशाद की कीमत की अदायगी का धंधा नहीं तो और क्या हो रहा है। इस चिलमन के पीछे एक अदृश्य तंत्र छुपा है, जो हर प्रभाव, हर सतर्कता और हर निगरानी के घाव बांट रहा है। चिट्ठा अगर युवा पीढ़ी के खिलाफ खड़ा है, तो यह पुलिस अनुशासन के लिए भी चुनौती बन रहा है। जाहिर है पुलिस विभाग को अपने फील्ड स्टाफ तक की काउंसिलिंग करने की जरूरत है। कई ढांचागत परिवर्तन करने से पहले हिमाचल के सीमांत क्षेत्रों की रात-दिन चौकसी की व्यवस्था कायम करने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है जब पुलिस पैट्रोलिंग के मायने सख्त व हर दम चाहिए। एक शुरूआत हुई है, लेकिन बड़े बदलाव के लिए पुलिस विभाग की कार्यशैली में बदलाव तथा काम करने की संस्कृति में उन्नयन चाहिए। बहरहाल, सरकार ने ग्यारह पुलिस कर्मियों पर सख्त आदेश पारित करके एक साथ कई चेतावनियां दे डाली हैं।

हिंदू मानस की राजनीति

देश के शहर-शहर हिंदू सम्मेलन आयोजित किए गए। उनसे पहले हिंदुओं की प्रभात फेरियां गलियों से गुजरी। आजादी के लंबे 74 सालों के बाद सोमनाथ का संघर्ष, गर्व, गौरव और सनातन का स्वाभिमान भी याद आ गया। सोमनाथ मंदिर ही नहीं, आराध्य महादेव का प्रथम ज्योतिर्लिंग भी है। वहां किसी आयोजन पर किसी को भी आपत्ति नहीं है। बीते 11 साल से अधिक समय से मोदी देश के पीएम हैं। अभी याद क्यों आया कि सोमनाथ का भी कोई स्वाभिमान है। उसके विध्वंस और पुनर्निर्माण का इतिहास 1000 साल पुराना है। देश के प्रथम पीएम की सोच और धर्मानिरपेक्ष राजनीति क्या थी, आज वह बिल्कुल बेमानी और अप्रासंगिक है। फिर पीएम मोदी ने सोमनाथ की आड़ में हिंदुओं की एकजुटता और टुष्टिकरण का मुद्दा उछाल कर हिंदुओं को एक होने का आह्वान क्यों किया। पीएम चुनावों में भी यह मुद्दा उठाते रहे हैं। बीजेपी को फायदा भी मिलता है। क्या मान लिया जाए कि पीएम ने सोमनाथ के बहाने देश का मानस बदलने की राजनीति की



है। उनका लक्ष्य है कि 2047 को विकसित हिंदू राष्ट्र घोषित किया जा सके। संविधान और दस्तावेज में बदलाव बाद में भी किया जा सकता है। प्रधानमंत्री ही नहीं, सरसंघचालक मोहन भागवत ने भी हिंदू एकजुटता का आह्वान किया है। उन्होंने यह भी विश्वास जताया है कि यदि हिंदू एक हो गए, तो आगामी 20-30 सालों में भारत को विश्व गुरु बनने से कोई रोक नहीं सकता।

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर बंटेंगे तो कटेंगे का नारा उछाला और हिंदू एकजुटता की बात कही। गली-गली, शहर-शहर जो सम्मेलन किए गए हैं, उनमें भी हिंदू एक की हुंकार गुंजती रही। हम स्पष्ट कर दें कि हमारा हिंदुत्व से कोई विरोध नहीं है। बेशक भारत में करीब 80 फीसदी हिंदू आबादी है, लेकिन यह ह्यहिंदू राष्ट्रह् नहीं है। भारत में मुसलमान, सिख,

ईसाई, पारसी, यहूदी, जैन, बौद्ध सरीखे अन्य समुदाय भी हैं। बेशक इनमें से कुछ समुदाय मानसिक तौर पर खुद को हिंदू मानते और घोषित करते हैं, लेकिन वे हिंदू नहीं हैं। विविधता ही भारत की खूबसूरती है। संघ परिवार को संविधान की नहीं, मानस की चिंता है। यदि सत्ता और संसद में भाजपा की शक्ति बरकरार रही, तो संविधान में कभी भी संशोधन किया जा सकता है, लेकिन हमें यह

आसान नहीं लगता। देश के एक और विभाजन का खतरा या संभावनाएं भी मौजूद नहीं हैं, लेकिन देश में आज भी गंभीर समस्याएं हैं जो चिंतित करती हैं। बेशक हम विश्व में चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हैं, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के संदर्भ में भारत 216 देशों की सूची में 140 वें स्थान पर है। हमारी प्रति व्यक्ति आय 2.65 लाख रुपए ही है। जिस जापान को हमने पछड़ा है, उसकी

यह आय करीब 30 लाख रुपए है। देश पर 225 लाख रुपए का कर्ज है। बेरोजगारी की दर करीब 7 फीसदी है। जिस इंटरनेशनल योजना की घोषणा बजट में गाजे बाजे के साथ की गई थी, उसका भद्दा सच यह है कि सिर्फ 95 युवाओं को ही ऑफर लेटर दिए गए हैं। 6618 युवाओं ने बीच में ही इंटरनेशनल छोड़ दी। यदि सामाजिक स्तर पर देखें, तो देश में 70 फीसदी से ज्यादा लोग विषाक्त पानी पीने को विवश हैं। ऐसी कई समस्याएं हैं, जो हिंदू-मुसलमान करने से हल नहीं होंगी। बेशक राष्ट्र और धर्म अपनी-अपनी जगह महत्वपूर्ण हैं, लेकिन एक राजनीतिक और वैचारिक अभियान के लिए कमोबेश देश की एकता, अखंडता, धर्मानिरपेक्षता की बलि नहीं दी जा सकती। देश में कई खामियां हैं, जिन्हें अर्थव्यवस्था की आड़ में छुपाया नहीं जा सकता। यकीनन अर्थव्यवस्था का विस्तार हमारी अभूतपूर्व सफलता और उपलब्धि है, लेकिन आज भी हम शिक्षा और स्वास्थ्य पर बजट का उतना हिस्सा खर्च नहीं कर पाते, जितना अपेक्षित है। लिहाजा स्कूल और अस्पतालों में जर्जर हालात हैं।

विजय की फिल्म जन नायगन पर सुप्रीम कोर्ट का सुनवाई से इनकार

नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने गुरुवार को अभिनेता विजय की फिल्म जन नायगन संबंधी याचिका पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और याचिकाकर्ता को मद्रास उच्च न्यायालय के समक्ष जाने को कहा।

उच्चतम न्यायालय ने इस मसले पर उच्च न्यायालय को 20 जनवरी तक निर्णय लेने का निर्देश भी दिया। इस याचिका में फिल्म को सेंसर प्रमाण पत्र देने संबंधी मद्रास उच्च न्यायालय के स्थगन के आदेश को चुनौती दी गई थी। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की अध्यक्षता वाली पीठ ने उस ह्यतीव्रताह् पर सवाल उठाया, जिस तीव्रता से उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश की पीठ ने नौ जनवरी को फिल्म के लिए सेंसर प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश दिया था। न्यायालय ने उल्लेख किया कि निमतार्ता ने



केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष के छह जनवरी के आदेश को चुनौती तक नहीं दी थी, जिसके तहत फिल्म को पुनरीक्षण समिति के पास भेजा गया था।

प्रोडक्शन हाउस के वीएन की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने दलील दी कि प्रमाणन में देरी के कारण उनके मुवक्किल बर्बाद हो गए हैं। जब न्यायमूर्ति दत्ता ने पूछा कि ऐसा दावा क्यों किया जा रहा है, तो श्री

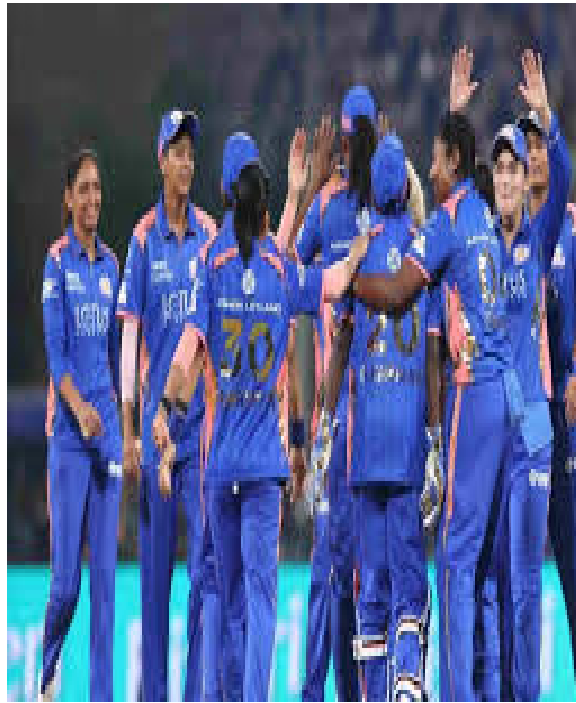
रोहतगी ने तर्क दिया कि यदि किसी फिल्म में देरी होती है, तो लोग रुचि खो देते हैं। इसका मूल्य समाप्त हो जाता है। पीठ ने हालांकि हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और श्री रोहतगी से अपनी सभी दलीलें मद्रास उच्च न्यायालय की खंडपीठ के समक्ष रखने को कहा। उच्चतम न्यायालय ने उच्च न्यायालय को निर्देश दिया कि वह अपने पास लंबित याचिका पर तेजी से और 20 जनवरी तक निर्णय ले।

मद्रास उच्च न्यायालय की दो न्यायाधीशों वाली पीठ ने नौ जनवरी को आदेश पारित होने के कुछ ही घंटों के भीतर फिल्म को ह्ययू/ए 16ह् प्रमाणपत्र जारी करने का निर्देश देने वाले एकल न्यायाधीश के आदेश पर रोक लगा दी थी। उच्चतम न्यायालय के समक्ष सीबीएफसी और उसके क्षेत्रीय अधिकारी की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता पेश हुए। सीबीएफसी ने तर्क दिया कि परीक्षण समिति

के पांच सदस्यों में से एक ने अध्यक्ष के पास शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें आरोप लगाया गया था कि सिफारिश किए जाने से पहले उनकी आपत्तियों पर उचित विचार नहीं किया गया था। बोर्ड ने तर्क दिया कि सिनेमैटोग्राफ (प्रमाणन) नियम, 2024 के तहत, यदि अध्यक्ष परीक्षण पैनल की सिफारिश से सहमत नहीं हैं, तो उन्हें फिल्म को पुनरीक्षण समिति के पास भेजने का अधिकार है। यह भी तर्क दिया गया कि सेंसर प्रमाणपत्र प्रदान करने की योग्यता पर न्यायिक समीक्षा का दायरा सीमित है। इन टिप्पणियों के मद्देनजर, उच्चतम न्यायालय ने याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया। अदालत ने उच्च न्यायालय को 20 जनवरी तक मामले का फैसला करने का निर्देश दिया है।

मुंबई की दूसरी जीत, डब्ल्यूपीएल मुकाबले में गुजरात जायंट्स को सात विकेट से हराया

मुंबई: वूमंस प्रीमियर लीग का छठा मुकाबला गुजरात जायंट्स और मुंबई इंडियंस के बीच खेला गया। नवी मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में मुंबई इंडियंस ने गुजरात टाइटंस को विमेंस प्रीमियर लीग में लगातार 8वां मैच हरा दिया। चौथे सीजन में गुजरात को पहली ही हार मिली है। मंगलवार को टॉस जीतकर मुंबई ने बॉलिंग चुनी। गुजरात ने 5 विकेट खोकर 192 रन बनाए। मुंबई ने 19.2 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर टारगेट हासिल कर लिया। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने फिफ्टी लगाई। उनके साथ अमनजोत कौर ने 40, निकोला कैरी ने 38 और हैली मैथ्यूज ने 22 रन बनाकर टीम की



जीत में अहम भूमिका निभाई। टीम से 4 गेंदबाजों ने 1-1 विकेट लिया। गुजरात से जॉर्जिया वेयरहम ने 43, भारती फुलमाली ने 36, कनिका आहूजा ने 35 और बेथ मूनी ने 33 रन बनाकर टीम को बड़े

स्कोर तक पहुंचाया। आयुषी सोनी 14 गेंद पर 11 रन बनाकर रिटायर्ड हर्ट हुईं, वे झुक्करु में रिटायर्ड हर्ट होने वाली पहली ही प्लेयर बनीं। गेंदबाजी में रेणुका ठाकुर, काशवी गौतम और सोफी डिवाइन ने 1-1 विकेट लिया।

मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के फैवरिट हैं रणवीर सिंह और रणबीर कपूर



समकालीन हिंदी सिनेमा की नब्ज को दशाते हुए एक बेबाक बातचीत में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बॉलीवुड से अपने मौजूदा पसंदीदा अभिनेताओं के नाम बताए। जब उनसे पूछा गया कि आज के समय में उन्हें किन अभिनेताओं को देखना पसंद है, तो फडणवीस ने कहा कि अभी के एक्टर्स

में मुझे रणबीर कपूर अच्छे लगते हैं, रणवीर सिंह भी अच्छे लगते हैं, लेकिन मेरे ऑल टाइम फेवरेट में अभी भी अमिताभ बच्चन जी और विनोद खन्ना जी हैं। रणवीर सिंह और रणबीर कपूर का जिक्र इस समय खास तौर पर प्रासंगिक है। रणवीर सिंह इन दिनों धुरंधर के लिए जबरदस्त सराहना बटोर रहे हैं। दर्शक और

समीक्षक दोनों ही उनकी दमदार स्क्रीन प्रेजेंस और ट्रांसफॉर्मेटिव परफॉर्मेंस की खूब तारीफ कर रहे हैं। हमजा फीवर लगातार चर्चा में बना हुआ है, जिससे धुरंधर 2 को लेकर उत्साह और भी बढ़ गया है। एक ही भाषा, हिंदी में 850 करोड़ रुपए से ज्यादा की कमाई करने वाले एकमात्र अभिनेता बनकर रणवीर

सिंह ने खुद को इस पीढ़ी का सबसे बेहतरीन और श्रेष्ठ अभिनेता साबित किया है। रणबीर कपूर ने कुछ साल पहले एनिमल में अपने विस्फोटक अभिनय से दर्शकों का दिल जीत लिया था और उन्हें जबरदस्त प्यार व सराहना मिली थी। अब फैंस बेसब्री से उस सिनेमैटिक दुनिया के और विस्तार का इंतजार कर रहे हैं, जो एनिमल पार्क के साथ आगे बढ़ेगी। अमिताभ बच्चन और विनोद खन्ना जैसे दिग्गज कलाकारों का नाम लेकर देवेंद्र फडणवीस ने पीढ़ी ें के बीच एक खूबसूरत सेतु बनाया है – जहां एक ओर वे सदाबहार महान कलाकारों का सम्मान करते हैं, वहीं दूसरी ओर उन समकालीन सितारों को भी सराहते हैं जो हिंदी सिनेमा के भविष्य को आकार दे रहे हैं।

दिल्ली बेली की मैडनेस देखने को फिर हो जाएं तैयार, हैप्पी पटेल में बहुत कुछ

दिल्ली बेली जब रिलीज हुई थी, तब उसने अपने डार्क ह्यूमर, अनोखे किरदारों और बेझिझक ऑफ-बीट अंदाज से मेनस्ट्रीम हिंदी सिनेमा के नियम ही तोड़ दिए थे। अब सालों बाद वही बिंदीसा और हटके सोच हैप्पी पटेल के साथ फिर बड़े पर्दे पर लौट रही है, जो उसी पागलपन और बेपरवाह माहौल को आज के टाइम के ट्विस्ट के साथ लाने वाली है। मोना सिंह, जिन्होंने मेनस्ट्रीम और एक्सपेरिमेंटल दोनों तरह की स्टोरीटेलिंग में काम किया है, कल्ट क्लासिक दिल्ली बेली और आने वाली फिल्म के बीच सीधा कनेक्शन देखती हैं। अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए मोना ने कहा कि दिल्ली



बेली को आइकॉनिक बनाने वाली वही स्प्रिट हैप्पी पटेल में भी गहराई से मौजूद है। दिल्ली बेली को मिले रिएक्शन्स याद करते हुए मोना ने कहा, ह्दिल्ली बेली के लिए लोग जो-जो शब्द इस्तेमाल करते थे, वही सारे शब्द हैप्पी पटेल पर भी बिल्कुल फिट बैठते

हैं, डार्क है, क्विकी है, ऑफ-बीट है, सब कुछ है। और मुझे इस मैड, क्रेजी यूनिवर्स का हिस्सा बनकर सच में बहुत मजा आया। उनकी बातें साफ इशारा करती हैं कि दर्शक हैप्पी पटेल से क्या उम्मीद कर सकते हैं, एक ऐसी फिल्म जो बेझिझक

पागलपन अपनाती है, हटके ह्यूमर दिखाती है और ऐसे किरदारों को सामने लाती है जो हमेशा एज पर रहते हैं। बिल्कुल दिल्ली बेली की तरह, यह फिल्म अपने बेखौफ अंदाज और अनप्रेडिक्टेबल कहानी पर चलती है, जो इसे फॉर्मूला वाली फिल्मों से अलग और ताजा बनाती है। आमिर खान प्रोडक्शंस के बैनर तले बनी हैप्पी पटेल: खतरनाक जासूस का निर्देशन वीर दास ने किया है। फिल्म में वीर दास के साथ मोना सिंह, शारिब हाशमी और मिथिला पालकर अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे। यह फिल्म 16 जनवरी 2026 को थिएटर्स में रिलीज होने वाली है।

वुलफार्ट ने आखिरी गेंद पर चौका लगाकर दिल्ली कैपिटल्स को दिलाई जीत

मुंबई - लिजेल ली (67) और शेफाली वर्मा (36) की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत दिल्ली कैपिटल्स महिला ने बुधवार को यूपी वॉरियर्स को सात विकेट से शिकस्त दी। लॉरा वुलफार्ट ने मैच की आखिरी गेंद पर चौका लगाकर अपनी टीम को जीत दिलाई। 155 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स के लिए शेफाली वर्मा और लिजेल ली की सलामी जोड़ी ने अच्छी शुरुआत करते हुए 94 रन जोड़े। 12वें ओवर में सोभना आशा ने शेफाली वर्मा को आउटकर यूपी वॉरियर्स को पहली सफलता दिलाई।



शेफाली वर्मा ने 32 गेंदों में छह चौकों की मदद से 36 रन बनाये। 15वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने लिजेल ली को आउट कर दिया। लिजेल ली ने 44 गेंदों आठ चौके और

तीन छक्के लगाते हुए 67 रनों की पारी खेली। 19वें ओवर में दीप्ति शर्मा ने कप्तान जेमिमाह रॉड्रिग्स 14 गेंदों में 21रन को आउटकर मैच को रोमांचक कर दिया।

दिल्ली कैपिटल्स महिला ने तीन विकेट पर 158 रन बनाकर सात विकेट से मुकाबला जीत लिया। लॉरा वुलफार्ट 24 गेंदों में 25 रन बनाकर नाबाद रही। और मैरीजान

कप्प ने नाबाद पांच रन बनाये।यूपी वॉरियर्स के लिए दीप्ति शर्मा ने दो विकेट लिये। सोभना आशा ने एक बल्लेबाज को आउट किया। इससे पहले आज यहां दिल्ली कैपिटल्स महिला ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। बल्लेबाजी करने उतरी यूपी वॉरियर्स ने निर्धारित 20 ओवरों में आठ विकेट पर 154 रन का स्कोर बनाया। कप्तान मेग लानिंग ने टीम के लिए सर्वाधिक 54 रनों की पारी खेली। उन्होंने 38 गेंदों का सामना किया और नौ चौके और एक छक्का भी लगाया। 36 गेंदों में सात चौकों की मदद से 47 रन बनाये।

कांगड़ा की बेटी प्रिया ठाकुर बनीं गोल्डन गर्ल



हमीरपुर: जिला कांगड़ा के छोटे से गांव सियोरबाला (खुडियां) के आम परिवार की बेटी प्रिया ठाकुर ने देश की सबसे बड़ी प्रतियोगिता अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 400 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर जिला कांगड़ा के साथ-साथ पूरे प्रदेश का नाम भी ऊंचा कर दिया है। प्रिया ने 400 मीटर दौड़ को 53.33 सेकंड में पूरा कर रिकॉर्ड बनाया। यह प्रतियोगिता कर्नाटक के मंगलूर में 12 से 16 जनवरी तक आयोजित की गई। इस प्रतियोगिता से पूरे देश की सभी यूनिवर्सिटी से 4 हजार के लगभग खिलाड़ियों ने विभिन्न एथलेटिक्स प्रतियोगिताओं में हिस्सा लिया था। प्रिया ठाकुर की जीत की खबर बुधवार को जैसे ही पता चली जिला कांगड़ा समेत हमीरपुर में

खेल जगत में खुशी का माहौल देखा गया। करीब 9 साल से प्रिया के कोच की भूमिका निभा रहे हमीरपुर जिला से ताल्लुक रखने वाले कोच अनिल कुमार शर्मा ने कहा कि यह उनके लिए गर्व का क्षण है। उन्होंने कहा कि साधारण परिवार से संबंध रखने वाली प्रिया बहुत अधिक मेहनती और ऊजावर्न खिलाड़ी है। उसका अगला लक्ष्य एशियन गेम्स में पार्टिसिपेट करना है। प्रिया की स्कूलिंग की बात करें तो सियोरबाला के सरकारी स्कूल से उसने जमा दो की शिक्षा पास की। यहीं पर पहली बार कोच अनिल शर्मा ने उसका हुनर पहचाना और उसे ट्रेड करना शुरू किया। 2016 में प्रिया को कांगड़ा की बेस्ट एथलीट के खिताब से नवाजा गया था। जमा दो के बाद प्रिया ने अपनी ग्रेजुएशन डिग्री कॉलेज हमीरपुर से कंप्लीट की। कॉलेज में प्रिया पहले 100 मीटर दौड़ती थी। उसने 100 मीटर की दौड़ 11.80 सेकंड में कंप्लीट की जोकि हिमाचल की बेस्ट एथलीट रही पुष्पा ठाकुर के बाद प्रदेश का पहला ऐसा रिकॉर्ड था। 2022 में कोच ने उसे 100 मीटर से 400 मीटर में शिफ्ट किया। उस दौरान प्रिया ने खेला इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में ब्रांज मेडल जीता था। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का 400 मीटर का रिकॉर्ड भी प्रिया के नाम है।

मराठी मुद्दे पर आए साथ, भूले गिले-शिकवे पर एग्जिट पोल ने दिया झटका

मुंबई: मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन (बीएमसी) चुनाव के नतीजे शुक्रवार को घोषित किए जाएंगे। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के लिए 9 साल बाद वोटिंग हुई। इस चुनाव में किसे बहुमत मिलेगा? इसे लेकर उत्सुकता है। मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चुनाव में बीजेपी की साख दांव पर लगी है। वहीं ठाकरे ब्रदर्स के लिए यह चुनाव वजूद की लड़ाई है। इसलिए सबका ध्यान शुक्रवार को होने वाली वोटों की गिनती पर है। वहीं गुरुवार को वोटिंग खत्म होते ही कई एग्जिट पोल सामने आए। इसमें लगभग सभी एग्जिट पोल ने बीजेपी-शिंदेसेना गठबंधन को बहुमत दिया है। वहीं उद्धव और राज ठाकरे की जोड़ी को बड़ा झटका लगा है।



मराठी एकता का नारा दिया। साथ आने के बाद उन्होंने ऐलान किया कि वे मुंबई नगर निगम का चुनाव भी साथ लड़ेंगे। दोनों ठाकरे भाइयों ने ब्रांच और कुछ मीटिंग करके

बीजेपी पर प्लान बनाया और हमला किया। उन्होंने मराठी वोटर्स से इमोशनल अपील की थी कि मुंबई को बचाने का यह उनका आखिरी मौका है। हालांकि, अब जो एग्जिट पोल

सामने आए हैं, उनमें वोटर्स ने ठाकरे भाइयों को कम रिसॉन्स दिया है। गुरुवार शाम आए एग्जिट पोल के आंकड़ों ने ठाकरे ब्रदर्स को टेंशन में डाल दिया है। क्योंकि

करीब सभी एग्जिट पोल ने देवेंद्र फडणवीस की बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना गठबंधन को पूर्ण बहुमत दिया है। दरअसल मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में कुल 227 सीटें हैं। बहुमत के लिए 114 सीटों की जरूरत है। दअरसल 2017 के चुनाव के दौरान शिवसेना एकजुट थी। उस समय पार्टी ने 84 सीटें जीती थीं। जबकि बीजेपी ने 82 सीटें जीती थीं और दूसरी सबसे बड़ी पार्टी बनी थी। शिवसेना ने मुंबई में सरकार बनाई थी। लेकिन अब 9 साल में हालात बदले हुए लगते हैं। शिवसेना में फूट के कारण ठाकरे की पार्टी की ताकत कम हो गई है। उन्होंने राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना (मनसे) के साथ बनाया बनाया है। पिछले चुनाव में मनसे ने 7 सीटें जीती थीं। इनमें से 6 कॉर्पोरेटर बाद में शिवसेना में शामिल हो गए

मुंबई में नहीं चला ठाकरे भाइयों का जादू, एग्जिट पोल में बीजेपी-शिवसेना को बहुमत

मुंबई: देश की सबसे अमीर नगर निगम बीएमसी में बीजेपी का पहला मेयर बैठ सकता है। बीएमसी चुनावों के लिए वोटिंग खत्म होने के बाद एग्जिट पोल में यही अनुमान सामने आया है। एक्सिस माय इंडिया के मुताबिक, बीजेपी गठबंधन को 131 से 151 सीटें मिल सकती हैं। यूबीटी को 58-68 सीटों पर जीत मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन को 12 से 15 सीटें मिल सकती हैं। बीएमसी में कुल वार्ड 227 हैं। ऐसे में बहुमत के 114 सीटें चाहिए। एक्सिस माय इंडिया के मुताबिक, बीएमसी चुनाव में यूबीटी का मराठी अस्मिता का दांव उनके पक्ष में रहा, मगर शिंदे सेना और बीजेपी ने भी 30 प्रतिशत मराठी वोटर्स का समर्थन हासिल किया। यूबीटी-मनसे को 49 फीसदी मराठियों ने वोट दिए। इससे उलट 68 प्रतिशत उत्तर भारतीयों ने बीजेपी-शिवसेना और 19 फीसदी ने ठाकरे भाइयों का समर्थन किया।



अन्नामलाई फैक्टर भी बीजेपी के साथ रहा। 61 प्रतिशत साउथ इंडियन वोटर बीजेपी गठबंधन के साथ गए। 21 फीसदी दक्षिण भारतीयों ने यूबीटी को समर्थन दिया। यूबीटी को कई इलाकों में मुस्लिम वोट मिले हैं। एक्सिस माय इंडिया के मुताबिक, बीजेपी गठबंधन को 131 से 151 सीटें मिल सकती हैं। यूबीटी को 58-68 सीटों पर

जीत मिल सकती है। कांग्रेस गठबंधन को 12 से 15 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को 41 फीसदी और ठाकरे भाइयों को 33 प्रतिशत वोट मिल सकते हैं। कांग्रेस को 13 प्रतिशत, एनसीपी को 3 प्रतिशत और अन्य को 10 प्रतिशत वोट मिल सकता है। बीएमसी में लंबे वक्त से शिवसेना की सत्ता रही है।

स्याही को पेन से बदल दिया, महाराष्ट्र में वोटिंग के बीच राज ठाकरे का हमला

मुंबई: महाराष्ट्र में मुंबई बीएमसी समेत 29 महानगरपालिका के चुनावों की वोटिंग के बीच स्याही को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। मुंबई में मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे ने आरोप लगाया है कि चुनाव आयोग ने वोट डालने के बाद लगाई जाने वाली स्याही को पेन से बदल दिया है। उन्होंने कहा इस नए पेन

भी कर सकती है। जब कोई ऐसे धोखे वाले तरीकों से सत्ता में आता है, तो हम इसे चुनाव नहीं कहते। मैं लोगों से, शिवसेना कार्यकर्ताओं से, और मातोश्री सेना कार्यकर्ताओं से अपील करता हूँ कि वे इन सभी बातों को लेकर सतर्क रहें। एक व्यक्ति को दो बार वोट डालते हुए पकड़ा गया। राज ठाकरे के आरोपों को

वाली एनसीपी के नेता और विधायक रोहित पवार ने भी यही आरोप लगाए। पवार ने एक वीडियो साझा किया है। इसमें उन्होंने ईक यानी स्याही के साफ होने का दावा किया है। एक मीडिया रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पुणे में एनसीपी कार्यकर्ताओं को बीजेपी ऑफिस में क्लीनर की बोतलें मिलीं। जिनका इस्तेमाल उन वोटर्स की उंगली से स्याही का निशान मिटाने के लिए किया जा रहा था जिन्होंने पहले ही वोट डाल दिया था, ताकि वे दोबारा वोट डाल सकें। एनसीपी कार्यकर्ता बीजेपी ऑफिस में घुस गए और बोतलें जकड़ लीं। कुछ ऐसा ही आरोप अजित पवार की अगुवाई वाली एनसीपी की नेता रुपाली चाकणकर ने भी लगाया है। वह महाराष्ट्र राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन भी हैं। महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों के लिए वोटिंग के बीच जहां स्याही की जगह पेन के इस्तेमाल पर बवाल मचा है तो वहीं दूसरी तरफ इस मुद्दे की गुंज सोशल मीडिया पर भी सामने आई है। वोट डालने के बाद डॉ. अभिनव वाघ ने एक फोटो डाली है। इसमें उनकी अंगुली पर लगी स्याही नहीं दिया रही है।



को लेकर शिकायतें हैं। अगर आप हैंड सैनिटाइजर लगाते हैं, तो स्याही गायब हो जाती है। अब, एकमात्र विकल्प यह बचा है कि स्याही लगाएं, बाहर जाएं, उसे पोंछ दें, और फिर अंदर जाकर दोबारा वोट दें। चुनाव प्रचार के लिए एक नया नियम लागू किया गया है। यह दिखाता है कि सरकार सत्ता में बने रहने के लिए कुछ

मुख्यमंत्री फडणवीस ने नागपुर में खारिज किया। उन्होंने अपनी उंगली पर लगी स्याही को पोंछकर दिखाया। फडणवीस ने कहा कुछ भी आरोप लगा देना सही नहीं है। वोट डालने के बाद लगाई जाने वाली स्याही को लेकर मुंबई से लेकर पुणे तक घमासान देखने को मिल रहा है। पुणे में शरद पवार की अगुवाई

मुंबई के कुर्ला में हादसा, ट्रेन में भीषण आग लगने से ठप हुई सेवा

मुंबई: मुंबई के कुर्ला में मलबा उठाने वाली ट्रेन की एक बोगी में अचानक आग लग गई, जिससे कुछ देर के लिए ट्रेन सेवाएं बाधित रहीं। दमकल की समय पर कार्रवाई के कारण आग पर काबू पाया गया और किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। जानकारी के अनुसार मुंबई सबअर्बन रेलवे नेटवर्क के कुर्ला में एक रेलवे रेक में आग गई। इसके कारण अप स्लो लाइन पर डलह को रात 8:38 बजे से 8:55 बजे तक बंद कर दिया गया। आग बुझाए जाने के बाद सेवाओं को बहाल कर दिया गया। रेलवे प्रशासन ने बताया है कि इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं लगी। कोई नुकसान नहीं हुआ। सभी सेवाएं फिर से



शुरू हो गई हैं। कुर्ला में रेलवे नेटवर्क के बीच मलबा उठाने वाली ट्रेन की बोगी में आग लगने की घटना के वीडियो भी सामने आए हैं। रेलवे ने आग की भयावहता को देखते हुए संचालक को रोक दिया था, लेकिन आग पूरी तरह से बुझ गई तो ट्रेनों की आवाजाही फिर से शुरू कर दी गई है। इस दौरान लोकल सेवाएं बुरी तरह

से प्रभावित हो गई। सोशल मीडिया पर आग के वीडियो काफी भीषण हैं। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई अनहोनी नहीं हुई। इतना ही नहीं इसकी चपेट में कोई अन्य सामान भी नहीं आया। रेलवे ने इस घटना पर संज्ञान लिया है आग कैसे और किस वजह से लगी इसकी जांच अधिकारियों की टीम के द्वारा की जाएगी।

मुंबई: गोरेगांव (पश्चिम) स्थित भगत सिंह नगर इलाके में शनिवार तड़के एक रिहायशी मकान में आग लगने से एक ही परिवार के तीन सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गई। मृतकों में 19 वर्षीय युवती और 12 वर्षीय किशोर भी शामिल हैं। घटना से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। मुंबई फायर ब्रिगेड के अनुसार, आग लगने की सूचना सुबह करीब 3.06 बजे मिली। आग एक ग्राउंड फ्लस वन मंजिला मकान में लगी थी। प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, आग सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर पर फैली, जहां बिजली की वायरिंग और घरेलू सामान इसकी चपेट में आ गया। इसके बाद पहली मंजिल पर रखे कपड़ों में



भी आग फैल गई। आग लगते ही आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और पानी की बाटियों से आग

बुझाने की कोशिश की। कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और बिजली आपूर्ति

बंद कर आग पर काबू पाया। करीब 3.16 बजे आग को पूरी तरह बुझा लिया गया। इस दौरान

घर के भीतर फंसे तीन लोगों को बाहर निकालकर पुलिस व निजी वाहन से गोरेगांव स्थित ट्रॉमा केयर अस्पताल पहुंचाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मृतकों की पहचान हर्षदा पावस्कर (19), कुशल पावस्कर (12) और संजोग पावस्कर (48) के रूप में हुई है। अधिकारियों के अनुसार, तीनों को गंभीर रूप से जलने की चोटें आई थीं। आग लगने के सटीक कारणों का फिलहाल पता नहीं चल पाया है। हालांकि शुरूआती जांच में आंशका जताई जा रही है कि आग बिजली की वायरिंग में शॉर्ट सर्किट से लगी हो सकती है। मामले की विस्तृत जांच जारी है।

सेकंड क्लास टिकट लेकर फर्स्ट क्लास में चढ़ा, TC ने मांगा फाइन तो कर दिया हमला

मुंबई: मुंबई की लोकल ट्रेनों में सफर करते समय टिकट कलेक्टर (TC) और फ्री में यात्रा करने वालों के बीच अक्सर बहस देखने को मिलती है। बिना टिकट सफर करने वाले पैसेंजर टीसी से बचने के लिए नई-नई तरकीबें अपनाते नजर आते हैं। हालांकि हाल ही में मुंबई में ऐसी ही एक घटना ने चौंकाने वाला मोड़ ले लिया है। मुंबई लोकल ट्रेन में दो लोगों ने

मिलकर एक टीसी की पिटाई कर दी। रेलवे पुलिस ने इस मामले में वडाला स्टेशन पर केस दर्ज किया है। यह घटना वडाला-छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनस (CSMT) स्लो लोकल ट्रेन में हुई। एक आरोपी की पहचान शब्बीर जफर शेख (उम्र 23) के तौर पर हुई है, जबकि दूसरे आरोपी का अभी पता नहीं चला है। एफआईआर से मिली जानकारी के मुताबिक,

शिकायत करने वाले धनंजय यादव (उम्र 40) एक टिकट इंस्पेक्टर हैं। उन्होंने बताया कि 1 जनवरी को शाम करीब 4.30 बजे वह और उनके साथी सुधीर मांझी (उम्र 35) वडाला रेलवे स्टेशन पर उटख की ओर जाने वाली एक स्लो लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास कोच में चढ़े टिकट इंस्पेक्शन के दौरान मांझी ने दो पुरुष पैसेंजर से उनके टिकट दिखाते को कहा।

बंद कर आग पर काबू पाया। करीब 3.16 बजे आग को पूरी तरह बुझा लिया गया। इस दौरान